



Universal Life Management - All be equally happy

संपूर्ण समाधान व्यवस्था

एक नयी सामाजिक राजनैतिक अर्थव्यवस्था

सभी को सारी सुख सुविधाएं और जनता के पास 24 x7 सत्ता की पावर

लोगों को सुधारने की ज़रूरत नहीं, व्यवस्था को लोगों के अनुसार होना चाहिए - प्रेमजीत सिरोही

साथियों ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके आ जाने पर, स्वभाविक रूप से, मनुष्य के जीवन में किसी भी प्रकार के दुःख, तकलीफें उत्पन्न ही नहीं होंगे और सभी प्रकार की सुख सुविधाएं सदैव पैदा होती रहेंगी। इस व्यवस्था में नया दर्शन है, नया अर्थशास्त्र है, नयी राजनैतिक व्यवस्था है, नयी सामाजिक संरचना है, नई शिक्षा व्यवस्था है और नया पारिवारिक मॉडल है। संयुक्त रूप से यह संपूर्ण समाधान व्यवस्था है। इस व्यवस्था के आ जाने पर बहुत सारे लाभ सब लोगों को होंगे, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं।

1. सभी विद्यार्थियों को उनकी इच्छा अनुरूप शिक्षा फ्री होगी। शिक्षा पूरी होने के बाद योग्यता और इच्छा अनुसार किसी एक कार्य में उसको ट्रेनिंग फ्री में मिल सकेगी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसका रोज़गार निश्चित रहेगा अर्थात बेरोज़गारी समाप्त। 25 वर्ष की आयु तक के सभी छात्रों को आरामदायक जीवन के लिए हर व्यवस्था फ्री होगी।
2. सभी को जन्म के बाद से ही सारी सुख सुविधाएं जो भी संभव होंगी उस समय पर, वह सभी को समान रूप से उपलब्ध रहेंगी अर्थात जिसको जब भी, जो कुछ भी चाहिए होगा, वह केवल मांग कर देने भर से उसको मिल जाएगा। दूसरे शब्दों में, सिस्टम द्वारा डिज़ाइन किए गए पोर्टल पर केवल ऑर्डर देकर उत्पादों / सेवाओं को प्राप्त किया जा सकेगा।
3. पूरी व्यवस्था में धन नहीं है, वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन नहीं है। उत्पादों / सेवाओं के लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है और काम करने पर कोई वेतन नहीं होगा।
4. एक दूसरे के साथ वस्तुओं और सेवाओं का आदान-प्रदान नहीं है। कोई निजी व्यवसाय, व्यापार, वस्तु विनिमय नहीं होगा। बेचने और खरीदने के लिए कोई बाज़ार नहीं है। सभी लोगों की मांग को पूरा करने के लिए एक एकीकृत व्यवस्था द्वारा सब कुछ उत्पादित और वितरित किया जाएगा।
5. इस व्यवस्था में सभी का ऑनलाइन प्रोफाइल होगा जिसमें उनके बारे में सब कुछ लिखा हुआ होगा जैसे कि उनका नाम, उनका एड्रेस, उनकी आयु, उनका फोटो, उनकी योग्यता, उनकी दक्षता, उनकी पसंद, उनकी नापसंद, आदि आदि।
6. विभिन्न उत्पादों / सेवाओं के लिए लोग अपना ऑनलाइन खाता बना सकते हैं और अपनी मांग रख सकते हैं। अनपढ़ लोगों के लिए भी सरल प्रक्रिया और सहायता उपलब्ध होगी। सभी कुछ मांग करने के लिए यह केंद्रीकृत ऑनलाइन सिस्टम ही होगा।
7. नई प्रणाली में, मांग विकेंद्रीकृत है यानी आप अपने इच्छित उत्पादों / सेवाओं के लिए बिना पैसे के ऑर्डर दे सकते हैं। लेकिन उत्पादन और वितरण केंद्रीकृत है।
8. संसाधनों पर कब्ज़ा पाने की होड़ नहीं होगी, जैसे आज प्राइवेट कंपनी प्रतिस्पर्धा करते हैं और ना ही यह एक समाजवादी कमांड अर्थव्यवस्था है जहाँ सरकार सभी लोगों के लिए निर्णय ले। यह प्रस्ताव साम्यवाद का एक रूप नहीं है जैसा कि आप सम्पूर्ण समाधान पुस्तक को पढ़ के समझेंगे।
9. 25-50 वर्ष की आयु के स्वस्थ लोगों को इस व्यवस्था का पूरा लाभ उठाने के लिए अपनी रुचि और योग्यता में आनेवाली कोई एक नौकरी चुननी होगी। सभी कार्य 25-50 वर्ष के लोगों के बीच वितरित किए जाएंगे। 50 वर्ष से अधिक आयु के योग्य व्यक्ति भी

इच्छित कर्म के लिए वालंटियर कर सकते हैं। शेष आबादी जैसे कि बच्चे, किशोर, वरिष्ठ नागरिक, बीमार लोग बिना किसी काम के अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त करेंगे। इसका मतलब यह है कि काम करने वाले उम्र की आबादी से प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक कर्म का चुनाव अनिवार्य है ताकि सभी के लिए आवश्यक उत्पाद और सेवाएं बनाई जाएं। किसी भी समय पति या पत्नी में से किसी एक के लिए रोजगार अनिवार्य होगा।

10. सभी की मांग व्यवस्था तक निरन्तर पहुँचती रहेगी और ऑर्डर के क्रम से व्यवस्था उत्पादों का निर्माण और डिलीवरी करती रहेगी।
11. System की सुरक्षा के लिए उत्पादों / सेवाओं के लिए ऑर्डरिंग Limit मौजूद होंगी और दुर्लभ वस्तुओं और सेवाओं को सामाजिक आधार पर जारी किया जाएगा ताकि हर कोई सुविधाओं का लाभ उठा सके और आनंद ले सके।
12. सभी संसाधन व्यवस्था के पास रहेंगे, अर्थात् मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन दोनों। मांग के अनुसार उत्पादन के लिए, मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधनों का संजोग करके सभी की इच्छाओं की पूर्ति होती रहेगी। एक इंटेलीजेंट डिज़ाइन के तहत, लोग अपनी मांगों को पूरा करने के लिए खुद ही अपना इच्छित काम करेंगे। यह व्यवस्था मनुष्य स्वार्थ के अनुसार है, इसलिए मनुष्य को सबसे सुगम रास्ते उसके इच्छित सुखों तक पहुँचाती है।
13. गुणवत्ता और दक्षता इसलिए संभव है क्योंकि सभी अपनी रूचि और योग्यता के हिसाब से काम कर रहे होंगे। जब यह व्यवस्था पूरी तरह से स्थित हो जाएगी तो लोगों को उनकी अभिरूचि अनुसार ही काम मिलेगा और इच्छा का काम करना सबको पसंद आता है। जब काम करने में मज़ा आता है तो हर आदमी अपने आप ही बेस्ट देता है। उसके अंदर से जितना भी बेस्ट निकल सकता है वह qualitative वस्तु व सेवा के रूप में परिणित होगा।
14. हर कामगार अपनी क्षमता अनुसार व्यवस्था द्वारा प्रदान production target को हामी देगा। व्यवस्था उसे productivity बढ़ाने के लिए मजबूर नहीं कर रही। एक दिन के टारगेट को वह 2 घंटे में करे या 6 घंटे में यह उसके ऊपर है। व्यवस्था कोई बंधा-बंधाया स्पीड नहीं फिक्स कर रही। हर कार्य दिवस में अंदाज़न 4-5 घंटे का काम होगा। हर काम करने वाले व्यक्ति का output तय होगा जो की धीरे धीरे करने पर भी प्राप्त करना संभव होगा। तो सभी अपनी स्पीड के अनुसार उसे कर के देंगे। व्यवस्था को फाइनल output और उसकी quality से मतलब है। आप कितनी तेज़ी से या धीरे करते हैं, इस से मतलब नहीं। बस आपको अपने पूर्व निर्धारित, स्व स्वीकृत output target को एक समय सीमा के अंदर पूरा करना है। इस से यह होगा की कोई किसी पर पुलिस की तरह निगरानी नहीं रख रहा होगा। लोगों को भय और डंडे के ज़ोर पे काम नहीं करवाया जा रहा। लोग अपनी इच्छा से काम कर रहे होंगे और अपना बेस्ट स्वाभाविक रूप से दे रहे होंगे और हर काम का quality check विभिन्न stages में होता रहेगा।
15. जनता का feedback लगातार आता रहेगा। पावर चूँकि decentralize है तो जब जनता उस वस्तु / सेवा का इस्तेमाल करेगी और अगर वह qualitative नहीं होगा तो वहाँ से उसका final review आ जायेगा। उसका review यदि negative आयेगा तो उस अधिकारी/ team/department पर सवाल खड़ा होगा। तो जो लोग ज़िम्मेदार होंगे उनसे पूछा जाएगा क्या दिक्कत हुई, और root cause analysis के बाद वह दिक्कत दूर करी जायेगी और ज़रूरी measures लिए जायेंगे ताकी end user संतुष्ट हो और वह दिक्कत फिर से न हो। इस तरह से इसमें quality control होता रहेगा।
16. व्यक्ति को किसी भी वस्तु / सेवा का मालिक बनने की ज़रूरत नहीं, जब उसे इच्छा होगी वह केवल उपयोग करेगा। अर्थात् जो जिस भी वस्तु अथवा सर्विस का इस्तेमाल कर रहा होगा और जितनी देर तक कर रहा होगा, उसका अधिकारी रहेगा। उसके छोड़ने के बाद वह फिर से व्यवस्था के पास वह वस्तु या सर्विस लौट आयेगी। लेकिन जिसको जो चाहिए जब चाहिए वह मिल रहा होगा, जिससे व्यक्ति सदैव सुखी ही बना रहेगा।
17. चूँकि व्यक्तिगत मांग को हमेशा निर्धारित समय में पूरा किया जाता है, इसलिए संसाधनों को जमा करने की आवश्यकता नहीं है और कोई संभावना भी नहीं है। व्यक्ति को भविष्य के बारे में चिंता नहीं सताएगी।
18. कुछ वस्तुएं और सुविधाएं ऐसी होंगी, जिन्हें आप निजी या पारिवारिक स्तर पर उपयोग के लिए आरक्षित कर सकते हैं और आपके द्वारा इसका उपयोग करने के बाद, यह रीसायकल या नवीनीकरण के लिए सिस्टम में वापस चला जायेगा। दूसरी कुछ सुविधाएं सामाजिक स्तर की सुविधाएं होंगी। ये सुविधाएं सार्वजनिक हैं क्योंकि उन्हें रखरखाव की आवश्यकता होती है जो एकल व्यक्ति या परिवार की क्षमता से परे है। उनकी व्यवस्था प्रशासनिक क्षेत्र के स्तर के अनुसार की जाती है। उदाहरण के लिए, परिवहन, स्विमिंग पूल, जिम, आदि प्रत्येक हाउसिंग काम्प्लेक्स के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। आपको स्विमिंग पूल या जिम के मालिक होने की आवश्यकता नहीं है। आपको बिना किसी सिरदर्द के अत्याधुनिक सुख सुविधाओं का आनंद मिलेगा।
19. सभी टाउनशिप समान, आधुनिक सुविधाओं वाले एक ही मानक के होंगे।
20. इस व्यवस्था में पॉलिटिकल मॉडल इस प्रकार का है जिसमें सारी पावर जनता में निहित रहेगी चौबीसों घंटे, नाकि किसी एक आदमी में या किसी एक ग्रुप में। तो इस प्रकार से सदैव सारी ताकत जनता में निहित होने के कारण कभी भी कोई तानाशाही नहीं हो सकेगी और सारी व्यवस्था जनता की, जनता के अनुसार, जनता के लिए चलती रहेगी। यह सही मायने में लोकतंत्र होगा।

21. संविधान में किसी भी संशोधन के लिए सार्वजनिक सहमति की आवश्यकता होगी। जनता की सहमति के बिना संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण कभी भी ऐसा कोई नियम नहीं होगा जो जनहित को ठेस पहुंचाए और यही इस व्यवस्था का उद्देश्य है। संविधान हमेशा जनता के नियंत्रण में रहेगा और एक तरह से जनता का सुख सुनिश्चित करता है। इस प्रणाली में शक्ति हमेशा नागरिकों के पास रहेगी न कि केवल 5 वर्षों में एक बार। यदि 10 % जनता कभी भी किसी नेता या नीति से नाखुश है तो वह निरस्त हो जायेगा। नए राजनीतिक मॉडल के अध्याय को पढ़कर आप इसे और गहराई से समझ सकते हैं।
22. शिकायत के लिए भी ऑनलाइन व्यवस्था ही रहेगी। अर्थात कहीं पर भी किसी के चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। नागरिक, संतुष्टि रेटिंग प्रदान करके प्राप्त उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता को रेट कर सकेगा। जनता और नेता इन फीडबैक और रेटिंग को कभी भी देख सकते हैं।
23. एक सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान की गई रेटिंग्स की गणना होती रहेगी। फिर नेताओं, कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रदर्शन की रेटिंग का पता चलता रहेगा। ये प्रदर्शन रेटिंग निर्धारित करेंगे कि नेता या अधिकारी उस भूमिका में रहने के लिए फिट हैं या नहीं। यदि नेता की प्रदर्शन रेटिंग एक निश्चित अंक से कम हो जाती है, तो चुनाव आयोग उस पद के लिए फिर से अन्य किसी की नियुक्ति करेगा। इस प्रकार नागरिक संतुष्टि रेटिंग नागरिकों को नेतृत्व पर नियंत्रण रखने के लिए एक संवैधानिक मार्ग प्रदान करती है।
24. सार्वजनिक स्तर के निर्णय लेने से संबंधित सभी डेटा, पारदर्शिता के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल पर सदैव मौजूद होंगे। लोग R.T.I. (सूचना का अधिकार) आवेदन को अलग से फाइल किए बिना सीधे इस जानकारी तक पहुंच सकते हैं। सिस्टम के साथ प्रत्येक इंटरैक्शन सहज और आसान होगा।
25. नई व्यवस्था में सभी पदों का आवंटन परीक्षा द्वारा होगा। नेता बनने के लिए भी उम्मीदवारों को चयन परीक्षा की प्रक्रिया से गुजरना होगा और शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार चुनाव के लिए पात्र हो जाएंगे।
26. यह एक वैश्विक सरकार होगी जिसमें सशस्त्र बल होंगे। जब अधिक राष्ट्र इस व्यवस्था का हिस्सा बनेंगे तो उन देशों के बीच सभी सीमा विवाद हल हो जाएंगे और किसी भी देश को अलग सेना रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार जब सिस्टम को विश्व स्तर पर स्वीकार कर लिया जाता है, कालांतर में सेना की आवश्यकता धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगी।
27. सभी लोग अपनी इच्छा अनुसार कार्यों को बदलते रह सकेंगे। केवल माप दंड यह है कि उन्हें उस पद के लिए योग्य होना पड़ेगा।
28. लोगों को स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता होगी। जब भी वे स्थानांतरित होंगे, उनके नए स्थान पर उनके निवास के लिए व्यवस्था होगी। नगरों को इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा कि लोगों को अपने कार्यालयों तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी और सड़क पर यातायात कम से कम होगा।
29. काम के घंटे कम से कम होंगे (approx. 5 hrs for 5 days per week) और लोगों के पास बहुत समय होगा क्योंकि अधिकांश प्रक्रियाएँ मानकीकृत होंगे और कई अंश स्वचालित भी होंगे।
30. इस व्यवस्था में किसी को लंबी कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा, बिलों का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, करों का भुगतान नहीं करना पड़ेगा और न ही कोई बैंक होगा। जीवन में सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए या अपनी पहचान साबित करने के लिए किसी भी संस्था को दस्तावेजों का अम्बार नहीं देना होगा। कम से कम कानून होंगे और पालन करना बहुत आसान होगा। सभी नियम तार्किक होंगे और सहज होंगे। अधिकांश प्रक्रियाएँ ऑनलाइन पूरी की जा सकती हैं और जीवन बहुत आसान, सुरक्षित और meaningful होगा।
31. यह व्यवस्था जीवन को आरामदायक और सुरक्षित बनाने के लिए technology का अधिकतम उपयोग करेगी। उदाहरण के लिए, कृषि ट्रैक्टर, ट्रक आदि एयर कंडीशनर से लैस होंगे और धूल वाहन में प्रवेश नहीं करेगा। इस प्रकार उपयोगकर्ता की सुविधा और सुरक्षा प्रमुख महत्व की होगी। यहां तक कि सबसे कठिन कार्य आसानी से प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ किया जाएगा। इस प्रकार कोई भी रोज़गार, हीन दृष्टि से नहीं देखा जायेगा।
32. सभी उत्पाद मानकीकृत होंगे और high quality के होंगे। प्राकृतिक चक्र को बनाए रखने के लिए, इस्तेमाल किए गए उत्पादों को recycle या विघटित किया जाएगा। इस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग नहीं होगा। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन एक चिंता का विषय नहीं रहेगा।
33. स्कूल, अस्पताल, फिटनेस क्लब, स्विमिंग पूल, पार्क, पुस्तकालय, संग्रहालय, रेस्तरां, थिएटर, विभिन्न प्रकार के क्लबों आदि सहित सभी सुविधाओं के साथ टाउन बनाए जाएंगे। सभी उम्र के लोग पूरी तरह से जीवन का आनंद ले सकेंगे।
34. लोग केवल व्यक्तिगत स्तर पर अपने धार्मिक विश्वासों का अभ्यास करने के लिए स्वतंत्र होंगे। उनके अभ्यास से दूसरों को वास्तविक असुविधा और संकट पैदा नहीं होना चाहिए। किसी भी ज्ञान को सामाजिक स्तर के लिए प्रमाणित करने के लिए उसे पहले निर्दिष्ट फोरम में साबित करना होगा।

35. समाज के लिए प्रमाणित किसी भी उत्पाद, सेवा, ज्ञान (दार्शनिक, वैज्ञानिक या अन्यथा) के बारे में कोई भी नीति, कानून, निर्णय लेने के लिए नेतृत्व परिषद, अनुसंधान प्लेटफार्मों और सार्वजनिक जनादेश से गुजरना पड़ेगा। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई मुद्दा है, तो खुले संवाद मंच का उपयोग करे। सभी चिंताओं का हल खोजने के लिए यह सामाजिक मंच है।
36. किसी भी नीति-नियम पर आपत्ति उठाने के लिए लोगों को धरना, आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। किसी भी विवादास्पद मुद्दे को हल करने के लिए सिस्टम में स्पष्ट चैनल होंगे। सभी के लिए **संवाद मंच** सदैव खुला रहेगा। नीति-नियम सम्बन्धी पूरा डेटा और शोध सार्वजनिक डोमेन में होगा। जो व्यक्ति किसी नीति पर आपत्ति उठाता है, उसे अपनी आपत्ति का औचित्य सिद्ध करना होगा। यदि वह **संवाद मंच** में सिद्ध नहीं कर सकता है, तो उसकी आपत्ति कोई आधार नहीं रखेगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बढ़ते ऑटोमेशन पे आपत्ति करता है, तो उसे अपना मामला संवाद मंच में प्रस्तुत करना होगा और अपना पॉइंट सिद्ध करना होगा। और यह संवाद जनता के लिए (24x7) उपलब्ध होगा।
37. अपना पॉइंट साबित किये बिना सरकार को दोष देकर जिम्मेदारी से कोई बच नहीं सकता है। विरोध प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको अपनी दलीलें पेश करने का पूरा मौका दिया जाता रहेगा और अंततः बातचीत, अनुसंधान और लोगों के जनादेश की एक अच्छी तरह से विकसित प्रक्रिया द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
38. कानून बनने से पहले 3 महीने के लिए सार्वजनिक मंच में रहेगा। मतदाताओं के पास कानून की समीक्षा करने के लिए 3 महीने का समय होगा। यदि कम से कम 10% वयस्क आबादी द्वारा कोई आपत्ति नहीं है, तो यह स्वचालित रूप से एक कानून बन जाता है। यदि 10% को आपत्ति है तो मामला पुनः विचार के लिए चला जायेगा।
39. व्यक्तियों के बीच आदान-प्रदान के लिए धन मौजूद नहीं है, और इस प्रकार संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए वित्तीय धोखाधड़ी और अन्य अपराधों की संभावना नहीं है। इस प्रकार यह एक बहुत ही सरल प्रणाली है जिसमें सदभाव बनाए रखने के लिए पुलिस बल का कम ही उपयोग होगा। पुलिस बल की भूमिका धीरे-धीरे विलुप्त हो जाएगी।
40. कोई अपराध नहीं होगा क्योंकि अपराध करने से, कोई भी कुछ भी अतिरिक्त हासिल नहीं करेगा जोकि वह पहले से ही सिस्टम द्वारा प्राप्त नहीं कर रहा है। इस प्रकार, भ्रष्टाचार, खद्य पदार्थ में मिलावट, धोखाधड़ी, लूट, शोषण, तानाशाही, सत्ता की लालसा आदि नहीं पैदा होंगे।
41. समाज में जाती, लिंग और भाषा आधारित, जो भेद भाव होता है वह खुद ब खुद समाप्त हो जायेगा। जो विभिन्न धर्मों, देशों, समुदायों, परिवारों और गुटों के बीच झगडे हैं वह समाप्त हो जायेंगे, क्योंकि मूल कारण ही नहीं बचेगा।
42. परिवार के सभी सदस्य सिस्टम से सीधे जुड़े होंगे और जब भी उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता होगी, वे सीधे सिस्टम से उसकी मांग कर सकते हैं। कोई आर्थिक निर्भरता नहीं होगी, जिसके कारण परिवार के सदस्यों के बीच संबंध वास्तविक होंगे और झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। जब ऐसा होता है तो एक-दूसरे के बीच विश्वास होगा और उनके रिश्ते मधुर और सौहार्दपूर्ण होंगे। एक व्यक्ति दूसरे को दबाने में सक्षम नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, हर कोई रिश्तों की मिठास का आनंद ले रहा होगा और कोई भी रिश्ता आर्थिक कारणों से संकट का अनुभव नहीं करेगा, नैतिक दबाव अनुभव नहीं करेगा।
43. इस तरह की व्यवस्था में रहते हुए, किसी को भविष्य की चिंताएं और तनाव नहीं होगा। लोगों को ऐसी स्थितियों का अनुभव नहीं होगा जैसे, "मैं कल के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे करूंगा, मैं घर चलाने के लिए खर्चों का प्रबंधन कैसे करूंगा, मैं चिकित्सा उपचार कैसे कर सकता हूँ, क्या होगा अगर मेरी नौकरी चली जाती है" ,इत्यादि। यदि कोई अन्य समस्या उत्पन्न होती है, तो उसे विशेषज्ञों द्वारा बहुत जल्द ही हल किया जाएगा। सभी नागरिक हमेशा व्यवस्था द्वारा समर्थित महसूस करेंगे और वे एक शांतिपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण जीवन का अनुभव करेंगे।
44. इस नई व्यवस्था में, चाहे वह बच्चे, युवा, वयस्क, बुजुर्ग, पुरुष, महिला, किसी भी लिंग के लोग हों, हर कोई अपनी इच्छानुसार, बिना किसी डर के खुशहाल जीवन जी सकेगा। महिलाएं और बच्चे हमेशा सुरक्षित और मुक्त महसूस करेंगे। लोग दूसरों का दबाव और नियंत्रण अनुभव नहीं करेंगे।
45. इस नई व्यवस्था में, किसी भी प्रकार का तनाव या परेशानी आदमी के जीवन में नहीं रहेगा। इस कारण बीमार होना बहुत कम हो जाएगा और जो भी हल्की फुल्की कोई बीमारी होगी तो उसका इलाज तुरंत ही हो जाएगा। आदमी की स्वाभाविक आयु भी अधिक हो जाएगी।

यह सब कैसे होगा विस्तार से जानने के लिए सम्पूर्ण समाधान पुस्तक पढ़ें। धन्यवाद!